जीवन में एक
छोटा बदलाव
और छोटी चिंगारी
दोनो ही बड़ा बदलाव
लाने का हुनर रखते है।
– अज्ञात

संकट की इस घड़ी का फायदा

वह कोरोना संकट से तबाह विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं में घुसपैठ कर रहा है, जहां–तहां शेयर बाजार के जरिये या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का रास्ता अपनाकर वह विभिन्न देशों की कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहा है।

राज जोशी।

सरकार ने समझदारी भरा कदम उठाते हुए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के नियमों में थोड़ी फेरबदल की है, ताकि संकट की इस घड़ी का फायदा कोई विदेशी कंपनी रणनीतिक महत्व की भारतीय कंपनियों पर कब्जा करने में न उठा ले। इस समय चीन दुनिया भर में ऐसी ही कोशिशों में लगा हुआ है। वह कोरोना संकट से तबाह विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं में घुसपैठ कर रहा है, जहां–तहां शेयर बाजार के जरिये या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का रास्ता अपनाकर वह विभिन्न देशों की कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहा है। कहा तो यहां तक जा रहा था कि उसने अमेरिका में भी बड़े पैमाने पर संपत्तियों का अधिग्रहण करना शुरू कर दिया है। हाल में चीन के केंद्रीय बैंक पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने भारत की सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हाउसिंग डिवेलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचडीएफसी) में 1.01 फीसदी हिस्सेदारी खरीदी। यह सिलसिला और न बढ़े, इसके लिए सरकार ने शनिवार को एफडीआई नियमों में कुछ अहम बदलाव किए। इसके तहत भारत के साथ सीमा साझा करने वाले किसी भी पड़ोसी देश से भारत में होने वाले निवेश के लिए सरकार से अनुमति लेना अनिवार्य बना दिया गया है।

नया नियम प्रत्यक्ष और परोक्ष, दोनों तरह के निवेश पर लागू होगा। पहले इस तरह की पाबंदी सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश से होने वाले निवेश पर ही लगी हुई थी। कोरोना वायरस के असर के कारण अधिकतर भारतीय कंपनियों के शेयरों में काफी गिरावट आई है। ऐसे में भारतीय कंपनियों का सस्ते में अधिग्रहण हो जाने और इनका नियंत्रण विदेशी हाथों में चले जाने का खतरा पैदा हो गया था। खासकर चीन को इस मामले में बड़े खतरे के तौर पर देखा जा रहा था जो कि सही सबित हुआ। चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, म्यांमार और अफगानिस्तान की सीमाएं भारत की सीमा से लगती हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पिछले सप्ताह विदेशी निवेशकों द्वारा भारतीय कंपनियों के सस्ते में हो रहे अधिग्रहण का मुद्दा उठाया था। उन्होंने एक ट्वीट में कहा था कि भारी आर्थिक सुस्ती के कारण देश की कई कंपनियों की हालत खराब हो गई है और वे विदेशी निवेशकों द्वारा अधिग्रहण के लिए आकर्षक हो गई हैं। संकट की इस घड़ी में सरकार को भारतीय कंपनियों का नियंत्रण विदेशी हाथों में जाने से रोकना चाहिए। यह मुद्दा सोशल मीडिया में भी छाया हुआ था। हाल में कई और देशों ने भी एफडीआई नियमों को सख्त बनाया है।

यूरोपीय संघ ने तो सुरक्षा का हवाला देते हुए पिछले साल ही एफडीआई की जांच पड़ताल किए जाने के नियम बना दिए थे। अब अमेरिका ने चीन से होने वाले निवेश की जांच सख्त कर दी है। ऑस्ट्रेलिया ने भी रणनीतिक संपत्तियों के सस्ते भाव बिक जाने के खतरे को देखते हुए विदेशी निवेशकों द्वारा किए जाने वाले अधिग्रहण के नियमों को मार्च में सख्त कर दिया था। उम्मीद है कि अब भारतीय कंपनियां अधिग्रहण के डर से मुक्त रहेंगी, हालांकि इसके लिए उन्हें पर्याप्त संरक्षण की जरूरत पड़ेगी।

कोशिश करें

अशोक वोहरा। जब आप चेतना का प्रकाश डालते हैं तब आपके जीवन से हर अनिश्चित चीज गायब होने लगती है। एक बार आप इस काल में माहिर हो गए तो आपकी उपस्थिति की चमक दोगुनी होकर बिखरने लगेगी और जब कभी आपको लगेगा कि आपके भीतर की अवचेतना आपको खींच रही है तो आप सहजता के साथ उसे नियंत्रित कर लेंगे। हालांकि सामान्य अवचेतना को प्रारंभिक चरण पर पहचाना नहीं जा सकता क्योंकि ये बहुत सामान्य प्रतीत होती है। आपको अपनी भावनात्मक और मानसिक स्थिति का निरीक्षण स्वयं करने की आदत डालनी होगी। आपके भीतर और बाहर क्या चल रहा है.. इस पर निरंतर ध्यान देना होगा। अगर आपके भीतर सब सही है तो बाहर के बुरे हालात भी आपको प्रभावित नहीं कर पाएंगे।

धर्म-दर्शन

संपादकीय

सेहत पर हमला

भारतीय अर्थव्यवस्था अभी काम–धंधे के लिहाज से सेकंड्री सेक्टर यानी तमाम तरह की मैन्युफैक्चरिंग, कॉन्स्ट्रक्शन और दुकानदारी की तरफ, जबकि आमदनी के लिहाज से टर्शरी सेक्टर यानी बैंकिंग, बीमा, कंप्यूटर से जुड़ी और अन्य ढेरों सेवाओं की तरफ बुरी तरह झुकी हुई है। गजब यह कि सेकंड्री और टर्शरी, दोनों ही दायरों की हालत अभी बहुत–बहुत खराब है। बैंकिंग एंड फिनांस को इनकी धुरी समझा जाता है क्योंकि ये सारे क्षेत्र वित्तीय पूंजी (फिनांस कैपिटल) के ही बल पर फलते–फूलते हैं। लेकिन भारत में बैंकिंग का बेड़ा पहले से ही गर्क हुआ पड़ा है। ऐसे कई सारे क्षेत्र, जो ऊपर से काफी खुशहाल दिखाई देते हैं, जिनके दिए विज्ञापनों के बल पर मीडिया इंडस्ट्री की गाड़ी कुलांचें मारती है, न सिर्फ बाजार की मामूली हरकतों से दिवालिया हो जाते हैं, बल्कि अपने पीछे–पीछे किसी वित्तीय संस्था को भी डुबो मारते हैं। अभी के माहौल में किस–किस का यह हाल है, पता करना मुश्किल है। हाउसिंग एंड रीयल एस्टेट को उबारना पहले ही टेढ़ी खीर साबित हो रहा था, अब तो यह किस्सा ही दूर का हो गया है। एयरलाइंस और हॉस्पिटैलिटी कंपनियों के डूबने की खबरें अभी से आने लगी हैं। और तो और टेलिकॉम और ऑयल एंड गैस जैसे अजेय समझे जाने वाले क्षेत्रों में भी डगमगाहट के चर्चे सुनाई पड़ने लगे हैं। पूरी दुनिया में इकॉनमी को बचाने के लिए बड़े–बड़े पैकेज घोषित किए जा रहे हैं। भारत में भी उद्योग संघों ने इसकी मांग की है और सरकार की तरफ से जीडीपी का 5 फीसदी, करीब 9.5 लाख करोड़ रुपये का पैकेज तैयार बताया जा रहा है। अर्थव्यवस्था इसकी भरपाई कैसे करेगी बाद में देखा जाएगा।

कोरोना वायरस का प्रकोप समाप्त करने की रणनीति यह नहीं है, यह बात सभी जानते हैं। इसका मकसद बीमारी के विस्फोट का दायरा घटाने और बचाव का ढांचा खड़ा करने के लिए समय हासिल करने तक सीमित है।

जीविका बचाने की जंग

चंद्रभूषण

भारत ही नहीं, पूरी दुनिया की अधिकतर आबादी अभी या तो लॉकडाउन में है या काफी रोकटोक के साथ काम पर जा रही है। कोरोना वायरस का प्रकोप समाप्त करने की रणनीति यह नहीं है, यह बात सभी जानते हैं। इसका मकसद बीमारी के विस्फोट का दायरा घटाने और बचाव का ढांचा खड़ा करने के लिए समय हासिल करने तक सीमित है। फ्लू के वायरस की तरह यह गर्मी आने के साथ नरम पड़ जाएगा, यह समझ पहले ही खारिज हो चुकी है। वैक्सीन या पक्का इलाज कोई है नहीं। ऐसे में बचकर चलना ही बाकी बचता है, जिसमें सारा संसार जुटा है। लेकिन इसके समानांतर यह चिंता भी हर जगह सिर उठाने लगी है कि ऐसा ही हाल रहा तो जून–जुलाई तक क्या लोगों की नौकरियां, काम–धंधे और आमदनी के बाकी जरिये बचे रहेंगे?

अपने यहां रबी की कटाई हफ्ते–दस दिन में हो जाएगी। गांव में इस सीजन में सबके हाथ में कुछ न कुछ पैसे पहुंच जाते हैं। लेकिन इस साल ऐसा हो पाएगा, इसमें संदेह है। मंडियां ठीक से चल नहीं पा रहीं। सूचना आ रही है कि लोगों ने थोड़ी कम कीमत पर निजी खरीदारों को अपनी उपज बेचना ज्यादा बेहतर समझा है। सबसे बुरी बात यह कि खेत मजदूरों के हाथ में

पैसा बिल्कुल नहीं गया है। खराब मौसम और बीमारी के डर से लोगों ने ज्यादा रेट पर कंबाइंड हार्वेस्टर से कटाई–मंड़ाई–ओसाई सब एक साथ करा लेना बेहतर समझा है। हालांकि छोटे और सीमांत किसानों के लिए यह रास्ता बंद सा ही है। खाने के लिए अनाज उगाने वाला परिवार हिम्मत करके अपने खेत में हार्वेस्टर लगा भी ले तो उसे अपने कई जरूरी खर्चों में कटौती करनी होगी। राष्ट्रीय पैमाने पर देखें तो खेती से जुड़ा सबसे बड़ा सवाल यह बनता है कि क्या अभी की खेतिहर गतिविधियां देश के विशाल ग्रामीण–कस्बाई बाजार को कामकाजी हालत में बनाए रखेंगी? गांवों का माहौल पूरी तरह हिला हुआ है। खेती अब नकदी मांगती है लेकिन इस साल शहरों से गांवों में इतना भी पैसा नहीं पहुंचने वाला कि खरीफ के लिए शुरुआती सिंचाई और खाद का इंतजाम हो सके। उलटे, फैक्ट्रियों में खटने वाले या रेहड़ी–ठेली चलाने वाले बहुतेरे लोग या तो शहरों में खैरात पर जिंदा हैं या गांवों के रास्ते में अटके हुए हैं। एक अर्से से बदहाली की शिकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को इस साल उनका परिवार भी पालना है। ऐसे में हर साल मिड–मई से मिड–जुलाई तक यहीं के दम पर 'मैरिज इकॉनमी' जो उछाल मारती है, उसकी इस बार कोई गुंजाइश नहीं है।

बहरहाल, भारत की तकरीबन तीन–चौथाई ग्रामीण आबादी का जीडीपी में दखल कुछ खास नहीं है। पिछले दस वर्षों में दो या तीन साल ऐसे गए हैं जब कम बारिश के चलते खेती की हालत बहुत खराब हो गई थी, फिर भी देश की जीडीपी ग्रोथ 6 पर्सेंट से ऊपर रही। लेकिन इस बार मामला ऊपर की तरफ बहुत ज्यादा गड़बड़ है, लिहाजा प्राइमरी सेक्टर यानी खेती, बागवानी, खनन और मछली पकड़ने का काम देश के लिए उम्मीद बंधाने वाला है। दूसरे चरण के लॉकडाउन में सरकार ने अपनी तरफ से इन सभी क्षेत्रों में यथासंभव सक्रियता बनाए रखने के उपाय किए हैं। ये कितने कारगर साबित होते हैं, इसका आकलन होना अभी बाकी है।

अष्टयोग-5031

	6	1		7	2	
	29	5	30		31	6
4			6	3	1	
	36		31		26	
7		4		5		2
6	38	3	31	6	32	4
	2			1		5

प्रस्तुत खेल सुडोकू व जोड़ की पद्धति का मिश्रण है. खड़ी व आड़ी पंक्तियों में 1से 7 तक के अंक लिखने अनिवार्य हैं. गहरे काले वर्ग में लिखी संख्या चारों और के 8 वर्गों की संख्या का कुल योग होगी. सीधी अथवा आड़ी पंक्तियों में 1 से 7 तक के अंक होना अनिवार्य है.

अष्टयोग 5030 का हल

3	6	1	4	7	2	5
6	35	5	30	2	25	1
7	5	2	6	3	1	4
1	33	6	31	4	29	2
2	6	4	1	5	3	7
4	33	3	31	6	37	6
5	2	7	4	1	6	3

Jagrutidaur.com, Bangalore

अपना ब्लॉग

वेतन दिलवाने का निर्णय

मोहन। सरकार ने सभी कर्मचारियों को वेतन दिलवाने का निर्णय किया है। कॉरपोरेट और व्यापार जगत के लोगों की इस मौके पर महत्वपूर्ण भूमिका है। हालांकि वर्तमान संकट से वे खुद भी बड़ा झटका महसूस कर रहे हैं। उन्हें वर्तमान परिस्थितियों में सक्षम बनाने के लिए वित्त मंत्री ने कई घोषणाएं की हैं। जैसे यह कि हम वैधानिक और नियामक अनुपालन से जुड़ी एक विस्तृत योजना लेकर आए हैं ताकि कंपनियों को इनकम टैक्स या आईबीसी कोड से जुड़े नियमों का पालन करने में कोई दिक्कत ना हो। फाइनेंशियल ईयर 2018–19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 30 जून होगी। देर से रिटर्न फाइल करने पर लगने वाला ब्याज भी घटा दिया गया है। पहले 12 फीसदी ब्याज देना पड़ता था जिसे घटाकर अब 9 फीसदी कर दिया गया है।